मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना

कृषि कुंभ (अगस्त, 2023),
खण्ड 03 भाग 03, पृष्ठ संख्या 102–103

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के ग्रामीण क्षेत्रो में प्रभाव

प्रिया सिंह, डॉ0 संगीता गुप्ता, डॉ0 रूपेश सिंह एवं पूजा
चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय,
कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत।
Email Id: pyup29@gmail.com

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2014 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के आने के बाद से सरकार द्वारा देश के किसानों को लाभ पहुचाने के लिये कई प्रकार की योजना प्रारम्भ की गई अनेक योजनाओ के साथ कृषि क्षेत्र में क्रान्ति लाने के लिये सरकार ,ारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत किसान अपने खेत की मिट्टी की जांच करा सकता है जिससे यह पता लगाया जा सके की मृदा में इस प्रकार के उवर्रक तत्वो की अधिक्ता है इस तत्व की मात्रा कम है इस प्रकार से पता लगाया जा सकता है कि हमे किस प्रकार के उर्वरक को अपने खेतो में प्रयोग किया जाना चाहिये। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना प्रधानमंत्री द्वारा 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ में प्रारम्भ किया गया था। देश के किसानो तक मृदा स्वास्थ्य कार्ड पहुचाने के लिये राज्य सरकार सहायता प्रदान करती है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रत्येक 3 वर्ष में केन्द्र सरकार द्वारा किसानो को उपलब्ध कराया जाता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानो के खेत की मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर प्राप्त होता हे जो कि प्रत्येक कार्ड 3 वर्ष के लिये मान्य होता है सरकार ने इस योजना के तहत पूरे भारत के 14 करोड़ किसानो को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है। योजना के दूसरे चरण मे बीते दो वर्षो मे कृषि मंत्रालय ने किसानो को 11.69 करोड मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किये है। केन्द्र सरकार द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण मे पहले चरण (वर्ष 2015 से 2017) मे 10.74 करोड़ कार्ड और दूसरे चरण (वर्ष 2017 से 2019) में 11.69 करोड़ कार्ड वितरित किये गये है। इन कार्डो की सहायता से किसान अपने खेतो की मृदा के बेहतर स्वास्थ्य और उर्वरता में सुधार के लिये पोषक तत्वों का उचित मात्रा में उपयोग करने के साथ ही मृदा की पोषक स्थिति की जानकारी प्राप्त कर रहे है।

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (National Productivity Council-NPC) द्वारा गये अध्ययन के अनुसार मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर सिफारिशो के तहत रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में 8 से 10 प्रतिशत तक की कमी आयी है, साथ ही उपज में 5 से 6 प्रतिशत तक वृद्धि हुयी है।

मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओ की स्थापना हेतु इस योजना के तहत राज्यों के लिये अब तक 429 नई स्टेटिक लैब (Static Labs), 102 नई मोबाइल लैब (Mobile Labs), 8752 मिनी लैब 1562 ग्राम स्तरीय प्रयोगशालाओ की स्थापना और 800 मौजूदा प्रयोगशालाओ का सुदृढ़ीकरण को मंजूरी दी गई है। केन्द्रीय कृषि मंत्रालय के मुताबिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड से किसानों की मिट्टी की सेहत के पैरामिटर जानने में मदद

मिल है। इससे मिट्टी मे पोषक तत्वों के सही प्रयोग से इसकी उर्वरा शक्ति में सुधार हुआ है।

कृषि मंत्रालय के अनुसार चालू वित्त वर्ष में आदर्श ग्राम विकास का एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है इसके तहत किसानो की साझेदारी में कृषि योग्य भूमि के नमूने लेकर उसकी जांच पड़ताल करने के कार्यक्रम को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस परियोजना के तहत मिट्टी के नमूनो का संग्रह करने और प्रत्येक कृषि जोत भूमि का विश्लेषण करने के लिये आदर्श ग्राम का चयन किया गया है।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड के कार्य करने का तरीका:

सबसे पहले अधिकारियों द्वारा आपके खेतो का सैंपल एकत्रित किया जाता है सैंपल को एकत्रित कर परीक्षण के लिये लैबोरेटरी मे भेजा जाता है। लैबोरेटरी में विशेषज्ञों द्वारा मिट्टी की जांच कर मिट्टी के बारे में सभी जानकारियां को प्राप्त किया जाता है जांच के बाद विभिन्न मिट्टीयों के सैंपल की शक्ति और कमजोरी की सूची तैयार की जाती है, मिट्टी उपस्थित कमियों को जान कर उसके सुधार के लिये सुझाव देने के साथ उसकी सूची भी तैयार की जाती है यह सब प्रक्रियायें पूरी होने के बाद रिपोर्ट को एक एक कर किसान के नाम के साथ ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाता है जो की उस कार्ड में उपस्थित होती है किसान अपने मोबाइल पर भी इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते है।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के लाभ:

इस योजना की मदद से किसानो को अपने खेत की मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी मिल पायेगी इससे वह मन चाहे अनाज फसल उत्पादन कर सकते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रत्येग 3 वर्ष में दिया जाता है जिससे किसान को अपने खेत की मिट्टी के बदलाव के बारे मे बीच बीच मे पता चलता रहेगा। इस योजना के तहत किसानों को अच्छी फसल उगाने मे मदद मिलेगी जिससे उन्हें और देश दोनो का फायदा होगा। इससे किसानो को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और देश उन्नति की ओर बढ़ेगा।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की सफलला:

फरवरी 2015 में योजना की शुरूआत के बाद प्रथम चरण में 84 लाख किसानो को मृदा स्वास्थ्य कार्ड तिरण का लक्ष्य रखा गया था लेकिन जुलाई 2015 तक केवल 34 लाख किसानो को ही मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किया गया। देश के सभी राज्यों में मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने में आंध्रप्रदेश सबसे आगे है तमिलनाडु और पंजाब दो अन्य राज्य है जिनमें खरीफ में सबसे अधिक संख्या में मृदा परीक्षण के लिये मृदा नमूने एकत्रित किये गये लेकिन तमिलनाडु मे अभी तक मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित नही किये गये है उत्तरप्रदेश, पंजाब, छत्तिसगढ़, तेलंगना और उड़िसा मृदा स्वास्थ्य कार्ड के वितरण एवं आवंटन में अन्य अग्रणी राज्य है। हरियाणा, केरल, मिजोरम, अरूणाचलप्रदेश, सिक्किम, गोवा तथा पश्चिम बंगाल आदि राजयों मे किसानों को 2013–16 के लक्ष्य के हिसाब से कम मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किया गया मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किसानों के लिये वरदान के रूप में साबित हो रही है। इतना ही नही इससे ग्रामीण युवाओं के लिये रोजगार भी मुहैया कराने में मदद मिल रही है।

Krishi Kumbh
Online E-Magazine
www.KrishiKumbh.com